अरुण कुमार शर्मा

बनाम

बिहार राज्य

(2003 की आपराधिक अपील संख्या 67)

5 अक्टूबर, 2009

[वी.एस. सिरपुरकर और दीपक वर्मा, जेजे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 302, 304 बी और 498 ए- विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाहित महिला की अप्राकृतिक मृत्यु-मृत्य कथित तौर पर गला घोंटने के कारण-दहेज की मांग का आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए धारा 304 बी और 498 ए आरोपी पति और सास-ससुर अपराध से बरी हो गए। पति हालांकि धारा 302 दोषी ठहराए गए परन्तु सास-ससुर सभी आरोपों में बरी। पति की अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः सभी गवाह बेहद संदिग्ध थे और विश्वसनीय नहीं थे - मृतक की गर्दन पर कई चोटें उंगलियों के जबरन दबाव के कारण हो सकती हैं-भले ही मृतक की मौत गला घोंटने से हुई हो, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि अकेले पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी-उसके खिलाफ प्राथमिकी करने में 5 दिन की देरी मजिस्ट्रेट को भी संदेह था-जांच गलत-पति को संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया।

अपील-आपराधिक अपील-अपीलीय न्यायालय की भूमिकाः निर्धिरत अत्यंत महत्वपूर्ण है-तथ्यों के सभी प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष खुले।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू1 की बहन अपने पति और सास द्वारा दहेज की मांग के कारण क्रूरता का शिकार थी और घटना की तारीख को, उसके सास-ससुर उसका पति ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष मामला पीडब्लू 1 की एकमात्र गवाही पर आधारित था। मृत्यु अप्राकृतिक थी और शादी के 7 साल के भीतर हुई थी। निचली अदालत ने कहा कि दहेज की कोई मांग साबित नहीं की गई है और उसके बाद मृतक के सास.ससुर को सभी आरोपों कबरी कर दिया और केवल पति (अपीलार्थी) को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए गए। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्वी की पुष्टि की गई।

इस न्यायालय में अपील में प्रश्न जो उत्पन्न हुआ जिस पर विचार करना था कि क्या अभियोजन अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा और इसलिए पति-अपीलार्थी बरी होने योग्य था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

1. पीडब्लू 1 का प्रमाण अत्यंत साधारण प्रकृति का है। यह ज्ञात नहीं है कि यह गवाह अपनी बहन के घर पर 6 बजे कर क्या कर रहा था। उसकी बहन की हत्या कर दी गई, देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं

किया। यह भी ज्ञात नहीं है कि इस गवाह ने तथाकथित हत्या के बाद, 15 घंटे तक पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। इस गवाह से साक्ष्य की सपुष्टि उनके पिता पी.डब्ल्यू. 4 करने की मांग की गई थी उसके सबूत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्वीकृत रूप से वह वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि उनके बेटे ने उसे बताया कि उसकी बहन को उसके ससुर, जीजा और उसके पति द्वारा पीटा जा रहा था। उन्होंने बहनोई का नाम भी जोड़ा। यह बहनोई कौन है, यह स्पष्ट नहीं किया गया था और न ही उस (बहनोई) को कार्यवाही में आरोपी बनाया गया। फिर से, यह काफी रहस्यमय है कि यह गवाह भी जो एक साक्षर गवाह था, पूरे एक दिन के लिए कुछ नहीं किया और पुलिस के पास नहीं गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ही उसने अपना बयान दिया। इस गवाह की साक्ष्य बेहद सामान्य कारण से बेहद संदिग्ध है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया और न ही वह पुलिस स्टेशन गया था। आम तौर पर, उसने अपीलार्थी अभियुक्त के माता-पिता का सामना किया होगा- और इस बेटी की मृत्यु के बारे में पूछा होगा। उन्होंने अभियुक्त पर अपना घर छोड़ने पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई। वह 15 घंटे से अधिक समय तक पूरा दिन चुप रहा, जब तक पुलिस उसके पास नहीं पहुंची और उसका बयान दर्ज कराया। पीडब्लू-3 का साक्ष्य भी साधारण कारण से बेहद संदिग्ध है कि वह भी, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें हत्या की सूचना दी गई थी, चुप रहे। उन्हें कुछ रहस्यमय कारणों से भी रखा गया था लगभग 15 घंटे तक चुप रहें।

पीडब्लू-1 का साक्ष्य, के साथ मिलान किया जाता है तो इस गवाह का साक्ष्य संदिग्ध लग रहा है। संक्षेप में, तीनों गवाह विश्वास प्रेरित नहीं करते हैं। [पैरा 14, 15, 16 और 17] [1032-एफ-एच; 1033-ए-सी; एफ-एच, 1034-ए-डी]

2. यदि अभियोजन की थयोरी यह थी कि उसे अभियुक्त द्वारा मुट्ठी व थप्पड़ से बुरी तरह पीटा तो कुछ मृत्यु पूर्व चोटें होनी चाहिए। दूसरी ओर, सकी चूड़ियाँ तक भी नही टूटी। पीडब्लू-1 ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसकी शीशे की चूड़ियाँ हाथों में थीं। पीडब्लू 2 का प्रमाण यह बताता है कि कई चोटें थीं जो उंगलियों के दबाव के कारण हो सकती हैं। भले ही यह माना जावे कि मृतक की मौत गला घोंटने से हुई थी, लेकिन यह विश्वसनीय सबूत नही है कि मृतक का अकेले आरोपी ने उसका गला घोंटा था। [पैरा 18 और 19] [1034-एफ; 1035-बी-सी]

3. इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी लगभग 9 बजे या रात 9:30 बजे (17.06.1994 का) पंजीकृत किया गया था, मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत, एफ. आई. आर. की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है। यह कभी नहीं हुआ। हालाँकि, अभिलेखों से देखा जाए तो यह एफ.आई.आर. केवल 22.06.94 पर मजिस्ट्रेट तक पहुंची यह बेहद संदिग्ध है। [पैरा20] [1035-डी-ई]

4.1. जाँच अधिकारी ने अपने बयान में साबित किया कि एस.एच.ओ. द्वारा लिखित रूप में एफ़.आई.आर. तैयार की गई थी। विशेष रूप से, यह एस.एच.ओ. या कोई अन्य अधिकारी ने घर की अच्छी तरह से जाँच नही की और न ही उन्होंने जाँच यह पता लगाने के लिए कि अंदर के कमरे के दरवाजे और कुंडी अक्षुण्ण हैं या नहीं, यह एक विशिष्टता मूर्खतापूर्ण जाँच थी। जाँच अधिकारी नेयहाँ तक कि एक जगह पंचनामा खींचने की भी जहमत उठाई। हालांकि उन्होंने कहा कि आरोपी उपस्थित नहीं थे, उन्होंने सुझाव दें कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि केस डायरी में, उन्होंने यह दर्ज नहीं किया था कि पुलिस स्टेशन में किस अधिकारी को सुचना प्राप्त हुआ था न ही इसका उल्लेख किया गया था कि किस महिला ने टेलीफोन पर जानकारी दी था। यहाँ तक कि मुखबिर का नाम भी मा केस डायरी में नहीं था। विशिष्ट उनसे सवाल किए गए कि क्या उन्होंने घटना के स्थान पर कमरों का निरीक्षण किया था या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि केस डायरी में ऐसा दर्ज नहीं है। यहां तक कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का समय भी नहीं था। उसने स्वीकार किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो न तो आरोपी और न ही उसके माता-पिता मौजूद थे। फिर उन्होंने दावा किया कि उनका सामान वहाँ था। यह बहुत ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने स्वीकार किया कि पीडब्लू1 ने घटना के

समय के बारे में नहीं किया बताया था और न ही उन्होंने मृतक को मुट्ठी और थप्पड़ से पीटने का तथ्य बताया। बहुत महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने स्वीकार किया कि पीडब्लू 1 ने रास्ते में पीडब्लू 3 के साथ मिलने के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि उनकी बहन की हत्या रंगीन टेलीविजन और मोटरसाइकल नहीं देने के कारण की गई थी। [पैरा 20 1035-ई-एच; 1036-ए-सी]

4.2. जांच एजेंसी ने कम से कम पड़ोसियों से जाँच करने में अच्छा काम किया होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि जाँच अधिकारी ने पड़ोसियों जिनमें से एक जो मृतक का रिश्तेदार था से जाँच नहीं की। घर की जाँच करने में जाँच अधिकारी की उदासीनता संदेह पैदा करता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जहाँ गलत जाँच के कारण एक युवा महिला की मृत्यु को दंडित नहीं किया जा सकता । [पैरा 23] [1037-सी-डी]

4.3. कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। ये प्रश्न न्यायालय में उलझे रहते हैं और एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति जांच अधिकारी जिसने सबसे गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह तरीके से काम किया है। [पैरा 24] [1037-ई-जी]

5. ट्रायल कोर्ट ने अब तक पीडब्लू-1 पर उसके द्वारा आरोपित आरोपी संख्या 1 व 2 की भूमिका के संबंध में विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह एक और कारण है जिससे पीडब्लू-1 के प्रमाण स्वीकार करना

बेहद मुश्किल है। उनके साक्ष्य का प्रमुख हिस्सा है - निचली अदालत द्वारा अविश्वास और निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। [पैरा 25] [1037-एच; 1038-ए]

6. निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले भी निराशाजनक हैं। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को संदर्भित किया गया है, गवाहों के साक्ष्य का मिलान नहीं किया है ताकि उचित स्थिति में आ सकें उन गवाहों की साक्ष्य की सत्यता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकें। उच्च न्यायालय का निर्णय भी इसी तरह का है। कोई गंभीर प्रशंसा नहीं है । साक्ष्य और, विशेष रूप से, अभिलेख के साथ-साथ सिद्ध दस्तावेज भी। ऐसा नहीं लगता कि मामले के रिकॉर्ड में गहराई से जाने का गंभीर प्रयास महत्वपूर्ण है। तथ्यों के सभी प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष खुले हैं। दुर्भाग्य से इस मामले में, निपटने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से गंभीर प्रयास किए गए। अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। [पारस 26 और 27] [1038-बी-जी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 67/2003।

न्यायिक न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के 1996 की आपराधिक अपील संख्या 49 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 1.5.2002 से।

अपर्णा झा, ब्रज के. मिश्रा, अभिषेक यादव अपीलार्थी।

प्रतिवादी के लिए मनीष कुमार (गोपाल सिंह के लिए)।

न्यायालय का निर्णय वी.एस.सिरपुरकर, जे. द्वारा दिया गया था।

1. एकमात्र अभियुक्त अपीलार्थी अपराधी ने अपील खारिज करने के व सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि और सजा के निर्णय की पुष्टि करना के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण है। सीताराम शर्मा, गायत्री देवी शर्मा और अरुण कुमार शर्मा तीन व्यक्ति हैं पर आई.पी.सी. धारा 302 सपठित धारा 34 और वैकल्पिक रूप से धारा 304 बी आई.पी.सी. सपठित धारा 34 और 498 ए के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। सीताराम शर्मा पिता हैं, गायत्री देवी माँ हैं और अरुण कुमार शर्मा (अपीलार्थी) पुत्र हैं के खिलाफ आरोप तीनों ने कहा कि उन्होंने सुषमा देवी रुण कुमार शर्मा की पत्नी की हत्या दहेज के लिए की थी। दहेज की माँग के कारण उसे क्रूरता का शिकार होना पड़ा। निचली अदालत ने सीताराम शर्मा और उनकी पत्नी गायत्री देवी शर्मा को बरी कर दिया। लेकिन अरुण कुमार शर्मा को मूल अपराध आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

3. दिनांक 17.06.1994 को, रात 9:30 बजे, लखीसराय पुलिस स्टेशन में एक टेलीफोनिक मेसेज प्राप्त हुई कि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उस आधार पर, एक प्रविष्टि, प्रविष्टि संख्या 516, पुलिस डायरी में बनाई गई थी और अपराध दर्ज किया गया। पुलिस तुरंत घटना

स्थल पर गई और एक से फरदबयान दर्ज कराया। लीलाधर प्रधान, अभियुक्त के ससुर अंततः पीडब्लू-4 के रूप में जांच की गई। यह शिकायत की गई थी कि उनकी बेटी श्रीमती सुषमा देवी की शादी आरोपी अरुण से हुई थी। अरुण कुमार हमेशा मोटरसाइकिल और रंग की मांग करते थे। उसकी पत्नी से टेलीविजन और उसे धमकी भी देता था कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। दावा किया जाता था कि मृतक हमेशा इस बारे में अपने माता-पिता को शिकायत करता थार। यह दावा किया गया था कि घटना से 8-9 महीने पहले, डांट, उत्पीड़न और दहेज, पंचायत की मांग की गई और पीडब्लू-4 ने आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई मांगों को पूरा करने में असमर्थता दिखाई। यह भी दावा किया गया कि सुबह लगभग 6 बजे अनिल सुषमा देवी और लीलाधर प्रधान (पीडब्लू-4) के बेटे कुछ सामान देने के लिए उसकी बहन का घर गया उसने तीन को मृतक को पकड़े हुए देखा और अरुण कुमार ने मृतक का गला घोंट दिया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इसलिए अनिल कुमार अपने घर वापस भागे और लीलाधर प्रधान (पीडब्लू-4) को घटना के बारे में सूचित किया और तुरंत इसके बाद माता-पिता के साथ-साथ अरुण कुमार भी सुषमा के घर गए, जहाँ वह मृत पड़ी थी।

4. आगे की जांच शुरू की गई। जाँच की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया कि

मृतक की गर्दन के सामने अलग-अलग आकार के कई चोट के निशान थे और गर्दन के नरम ऊतकों में अतिरिक्त खून था और उसकी हाइड हड्डी ट्रैकेया टूट गई थी।

5. आरोपी घर में मौजूद नहीं पाए गए और घर खुला पाया गया। आखिरकार, उन्हें तभी गिरफ्तार किया जब वे अदालत में 10 दिनों से अधिक समय के बाद आत्मसमर्पण करते हैं।

6. आई.पी.सी. की धारा धारा 304 बी, 498 ए सपठित 34 के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, मुकदमे के चरण में, आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत अपराध को भी जोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के दावे के समर्थन में, अनिल कुमार प्रधान की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई जबकि डॉ. धरम की जांच की गई। पोस्टमॉर्टम करने वाले नाथ चौधरी की जाँच की गई पीडब्लू-2 के रूप में। एक ओम प्रकाश विद्यालंकर की भी जांच की गई। पीडब्लू-1 के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए पीडब्लू-3 के रूप में। उनके कथन के अनुसार, उन्होंने अरुण कुमार को भागते हुए देखा था। हत्या कर दी। दिवंगत सुषमा के पिता लीलाधर की पीडब्लू-4 के रूप में जांच की गई। पुलिस गवाहों सहित, अभियोजन पक्ष द्वारा सभी 8 गवाहों से पूछताछ की गई।

7. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष केवल एक आंख पर निर्भर था गवाह, अर्थात् अनिल कुमार प्रधान और दूसरी ओर इस परिस्थिति में कि अपनी शादी के 7 साल के भीतर, सुषमा की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी।

8. सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त का बचाव कि यह हत्या का मामला बिल्कुल नहीं था। अभियुक्त के अनुसार, मृतक ने गहने अपने पिता पास रखे थे लेकिन वे मृतक को वापस नहीं किए गए और इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली। दो गवाह थे। डब्ल्यू.-1 के रूप में जांच की गई, वीणा देवी, जो पड़ोसी थी और जिसने दावा किया कि उसने मृतक से लगभग सुबह 8 बजे बात की थी, और डी.डब्ल्यू.-2 नर्मदा देवी, जो अभियुक्त अरुण कुमार की मातृ दादी थी। जिसने यह बयान दिया था कि उस दिन उसने अवकाश लिया था। वह सुषमा से मिलने गई थी, सुषमा पे अपने पति लिए उपवास किया और उसके बाद उसने खाना बनाया और नहाने के बाद वह अपने बेटे के साथ अपने कमरे में आई व दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गवाह ने आगे दावा किया कि उसने 2 व्यक्तियों की मदद से जबरन दरवाजा खोला और सुषमा के शव को पंखे से लटकते हुए देखा।

9. निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई मांग नहीं की गई इस मामले में दहेज का आरोप साबित नही हुआ और इसलिए आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 304 बी आई.पी.सी. व धारा 498 ए के तहत

अपराध के तहत अपराध से बरी कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पिता और माता के वहाँ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और पीडब्लू-1 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह अभियुक्त संख्या 1 और 2 अर्थात पिता और माताके विरुद्ध कुछ भी ठहराता है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने आगे बढ़ कर कहा कि अभियुक्त 1 और 2 को सभी आरोपों से बरी कर दें और केवल वर्तमान अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 303 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।

10. इस फैसले के खिलाफ अपील विफल हो गई, जिसके लिए हमारे समक्ष वर्तमान अपील आवश्यकता पड़ी। सुश्री झा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए, निर्णयों की कड़ी आलोचना की। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण अदालत ने बताया कि कई विसंगतियां थीं। अभियोजन पक्ष के मामले में पाया जाना अस्पष्टीकृत रह गया था।

11. राज्य के विद्वान वकील ने निर्णयों का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपराधों को पूरी तरह से साबित कर दिया है। इसलिए, हमें यह तय करना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने वास्तव में अपराध को सदेह से परे साबित किया है।

12. अभियोजन पक्ष का मुख्य आधार पीडब्लू 1, अनिल कुमार प्रधान का साक्ष्य है। सुश्री झा ने हमें साक्ष्य में बताया। उसके अनुसार, वह सुबह

6 बजे अपनी बहन के घर गया था। सुबह कुछ लेख देने के लिए। उस समय उसने देखा कि उसकी बहन को उसके ससुराल वाले संयुक्त रूप से पकड़ रहे थे और अरुण कुमार उसका गला घोंट रहा था। तब उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अरुण कुमार उसकी गर्दन को दबाया और वह जमीन पर गिर गई। फिर वह कहने लगा कि उसने शोर मचाया और उसकी ओर भागा। घर जाकर रास्ते में ओम विद्यालंकर से मिले जिन्होंने उनसे पूछा वह क्यों रो रहा था, जिस पर उसने बताया कि उसकी बहन हत्या की गई।

13. बचाव पक्ष के वकील ने जमीनी स्तर पर इस साक्ष्य की आलोचना की कि यह प्रकृति में बहुत सामान्य था। यह सुझाव दिया गया था कि यह स्पष्ट नहीं है कि सुबह 6 बजे किन कारणों सेमृतक से संपर्क किया जाना था। विद्वान वकील ने भी बताया कि यह अविश्वसनीय था कि उसकी बहन की हत्या की जा रही थी और उसने रोने और अपने माता-पिता के पास भागने के अलावा कुछ नहीं किया। एक बार फिर उन्होंने विद्यालंकर उनसे मिले तब यह नहीं बताया कि ओम प्रकाश कहां हैं। जाँच अधिकारी ने ओम प्रकाश विद्यालंकर से मुलाकात के बारे में एक गंभीर चूक थी। आखिरी परन्तु अंतिम नहीं, विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि यह गवाह, और अन्य गवाह भी, पूरे समय मृतक के शव के साथ बैठे रहे उस दिन और रात 9:30 बजे तक मामले की रिपोर्ट नहीं की पुलिस किसी और के पुलिस स्टेशन पर फोन करने पर मौके पर पहुंची।

14. जब हम इस गवाह की जिरह देखते हैं, तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसका घर अभियुक्त व्यक्तियों के घर से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर दूर था और वहाँ पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। यह वास्तव में अजीब है कि इस गवाह ने सुबह के शुरुआती घंटों में 6 बजे सामान देने के लिए जाना चुना। वह यह नहीं बताता कि वह अपनी बहन के घर कौन सी वस्तुएँ ले गया था। मान ले, 25-30 सेकेण्ड के लिए वह वहाँ था। इसके तुरंत बाद उसकी मां और पिता मौके पर पहुंचे। यह वास्तव में रहस्यमय है कि इन 15 मिनट के समय के दौरान आरोपी व्यक्ति कहाँ गए, लेकिन यह समझने से परे है कि ये तीनों पुलिस को सूचित किए बिना और कुछ भी लिए बिना वहाँ क्यों बैठे रहे। यह बिल्कुल संदिग्ध है कि उसने या उसके माता-पिता ने पूरा दिन क्या किया। उसे अपने बहनोई, वर्तमान अभियुक्त के ठिकाने का भी पता नहीं था। उन्हें सुषमा की शिक्षा के बारे में पता भी नहीं था, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि सुषमा एक भावुक लड़की थीं। उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी मांग के बारे में या सुषमा ने उसे या उसके माता-पिता को मांगों के बारे में बताया के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है धारा 164, सीआर.पी.सी. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164, सीआर.पी.सी. के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। बहुत अजीब बात है कि उन्होंने अदालत के समक्ष दिए गए। अपने सभी बयानों को व्यावहारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि क्या वह

रास्ते में ओम प्रकाश विद्यालंकर से मिले थे आदि। इस गवाह का प्रमाण प्रकृति में बेहद अनौपचारिक है। यह पता चला नहीं है कि यह गवाह अपनी बहन के घर पर 6 बजे क्या कर रहा था। अपनी बहन की हत्या होते देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। यह भी ज्ञात नहीं है कि इस गवाह ने 15 घंटे के लिए तथाकथित हत्या के बाद ऐसा क्यों नहीं किया कि पुलिस को सूचित करें। मान लीजिए कि वह वहाँ मौजूद नहीं थे। वह केवल उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बहन उसके ससुर, उसका पति और देवर द्वारा पिटाई की जाती है। उन्होंने बहनोई का नाम भी जोड़ा। यह साला कौन है, यह स्पष्ट नहीं किया गया था और न ही वह (भाई) था। कानून कार्यवाही के लिए अभियुक्त बनाया गया। फिर से, यह काफी रहस्यमयी है कि यह गवाह भी जो एक साक्षर गवाह था, पूरे दिन कुछ नहीं किया और घर नहीं गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ही उसने उसका ऐसा बयान दिया। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी के साथ सांठगांठ की थी और पहले एक विरोध याचिका दायर की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय ने बार-बार कहने के बावजूद, पुलिस आरोपी गायत्री देवी और सीता रामको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि वह लेखाकार के रूप में कार्य करता था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने टेलीविजन और मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में अपने बयान में कहा नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण रूप से, वह कहता है कि जब वे पहुंचे तो

आरोपी यानि उसका दामाद और उसके माता-पिता घर में मौजूद थे। यह पीडब्लू-1 अनिल कुमार सहित किसी का दावा नहीं है। यह फिर से रहस्यमय है जब वह कहता है कि उस दिन सुबह लगभग 7 या 7.15 बजे उनके दामाद और उनके दामाद माता-पिता ने घर छोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि वे कहाँ गए थे। उनका यह भी दावा है कि वे घटना के अगले दिन या जब तक वह घटना स्थल पर थातक नहीं लौटे। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने अपने फरदबायान में कहा था या नहीं कि घटना स्थल पर उनका पीछा करते हुए ओम प्रकाश विद्यालंकर भी आए थे।

15. इस गवाह का सबूत बेहद संदिग्ध है। इस साधारण कारण से कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं किया और न ही वह पुलिस स्टेशन गया था। आम तौर पर, वह वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी के माता-पिता का सामना करता और बेटी की मृत्यु के बारे में पूछता। उन्होंने भी अभियुक्त के अपना घर छोड़ने पर कोई आपत्ति न उठाएँ। जब हम इस गवाह द्वारा बनाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट देखते हैं, यह देखा गया है कि मोटर साइकिल और टेलीविजन की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। अपनी रिपोर्ट में वे कहते हैं कि व्यक्तियों की संख्या, कई पुरुष और महिलाएँ उपस्थित थीं। जो बात हमें पूरी तरह से परेशान करती है वह यह है कि यह गवाह 15 घंटों तक पुलिस उसके पास पहुंची और उसका बयान दर्ज किया तब तक पूरे दिन चुप रहा।

16. ओम प्रकाश विद्यालयंकर (पीडब्लू-3) का प्रमाण है -वह भी इस साधारण कारण से बेहद संदिग्ध है कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें हत्या के बारे में सूचित किया गया था, फिर भी चुप हो जाओ। उन्होंने दावा किया किवे कुछ देर बाद सुषमा के घर पहुँचे वह पूरे दिन शव के साथ थे। जब यह स्पष्ट है कि यह गवाह उपस्थित था क्योंकि रिपोर्ट मेंउसके हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। हालांकि, वह कुछ रहस्यमय कारणों से लगभग 15 घंटे तक चुप रहे। जब अनिल कुमार प्रधान (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के साथ मिलान किया जाता है, तो इस गवाह का साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है।

17. संक्षेप में, तीनों गवाह आत्मविश्वास। प्रेरित नहीं करते हैं। पीडब्लू-2 वह डॉक्टर है जिसने शव परीक्षण किया था। यह स्पष्ट है कि अपने साक्ष्य में, उन्होंने सुषमा के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण के घाव पाएः

> "1. गर्दन के सामने के हिस्से पर 3/4 "-1/2" x1/4"; कई चोट के निशान अलग-अलग आकार के होते हैं।''
>
> 2. विच्छेदन पर एक्किमोसिस मौजूद पाया गया। कोमल ऊतकों में रक्त की अतिरिक्त निकासी थी। श्वासनली की हाइड हड्डी के फ्रैक्चर के साथ गर्दन का।"

18. यह महत्वपूर्ण है कि सुषमा के पास कोई और चोटें नहीं था। यदि अभियोजन का सिद्धांत यह था कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मुट्ठी और थप्पड़ से बुरी तरह पीटा जाता है तब कुछ मृत्यु पूर्व-चोटें शव परीक्षण में पाई जानी चाहिए थीं। जिस पर दूसरी ओर, उसकी चूड़ियाँ भी नहीं टूटी थीं। अनिल कुमार प्रधान (पीडब्लू-1) ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उनके हाथों में कांच की चूड़ियाँ बरकरार थीं। अपनी प्रतिपरीक्षा में, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मृत्यु चोट संख्या 1 गर्दन पर जबरन दबाव के परिणामस्वरूपदम घुटने के कारण थी। डॉक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः

> "11. इस मामले में, पोस्टमार्टम करते समय जाँच में मुझे कई चोट के निशान मिले जो उंगलियों के जबरदस्त दबाव के कारण हो सकते हैं। कई चोटें लिगचर के कारण नहीं होती हैं और इसे बंधन चिह्न नहीं कहा जाता है।''
>
> 13 .बंधन चिह्न में अवसाद के साथ चौड़ाई होती है।''

19. अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में उन्होंने स्वीकार किया कि अगर उंगलियों का उपयोग किया जाता है, तो अंगूठे और उंगलियों द्वारा दबाव का निशान आमतौर पर पवन नली के दोनों ओर पाए जाते हैं। इस सबूत, से यह प्रतीत नहीं होता है कि पवन नली के दोनों तरफ इस पर ऐसा कोई निशान था। डॉक्टर का प्रमाण यह बताता है कि कई चोटें थीं जो

उंगलियों के बलपूर्वक दबाव से हो सकती हैं। भले ही यह माना जाए कि सुषमा गला घोंटने से मृत्यु हो गई, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह था अकेला आरोपी ने सुषमा की गला दबाकर हत्या कर दी।

20. इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो एफ़.आई.आर. दर्ज की गई थी रात के लगभग 9 बजे या 9:30 बजे पंजीकृत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया था। धारा 157 सीआर.पी.सी. के तहत, एफ.आई.आर. की प्रति मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि, अभिलेखों से देखा जा सकता है कि यह एफ़.आई.आर. मजिस्ट्रेट तक केवल 22.06.94 को पहुंची, यह बेहद संदिग्ध है। अपने बयान में, जाँच अधिकारी ने साबित किया कि एफ़.आई.आर. माहेश्वरी मंडल, एस.एच.ओ. द्वारा लिखाकर तैयार की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण रूप से, यह एस.एच.ओ. या किसी अन्य अधिकारी ने कभी भी घर की अच्छी तरह से जांच नहीं की। न ही उन्होंने यह पता लगाने के लिए अंदर के कमरों की जांच की है कि दरवाजे और कुंडी ठीक थे या नहीं। यह एक विशिष्ट मूर्खतापूर्ण जाँच थी। जाँच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि केस डायरी में उन्होंने किस बारे में दर्ज नहीं किया था। अधिकारी को पुलिस स्टेशन में जानकारी मिली और न ही केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि किस महिला ने टेलीफोन पर जानकारी दी संदर्भित किया गया था। यहाँ तक कि मुखबिर का नाम भी केस डायरी में नहीं था। विशिष्ट प्रश्न क्या उन्होंने जंहा घटना हुइउस स्थान पर कमरों का निरीक्षण किया था या

नही। उन्होंने स्वीकार किया कि केस डायरी में उल्लेख नहीं किया गया था। यहां तक कि शव को पोस्टमार्टमके लिए भेजने का समय का भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने स्वीकार किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो न तो आरोपी और न ही उसके माता-पिता मौजूद थे। फिर उन्होंने दावा किया कि उनका सामान वहाँ था। यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने स्वीकार किया कि अनिल कुमार ने घटना के समय के बारे में नहीं बताया था और न ही इस तथ्य को उन्होंने बताया था कि सुषमा को मुट्ठी और थप्पड़ से पीटना था। बहुत महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने स्वीकार किया कि अनिल कुमार ने रास्ते में ओम प्रकाश विद्यालंकर के साथ इस मुलाकात के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने यह भी नहीं कहा था किउसकी बहन की हत्या रंगीन टेलीविजन और मोटर साइकल न देने के कारण की गई थी । उन्होंने आगे स्वीकार किया कि अनिल कुमार (पीडब्लू-1) ने यह नहीं कहा था कि उनके पिता ने उन्हें जाने के दौरान बताया था। शिक्षा के लिए कि कुछ सामान उसकी बहन को दिया जाना था। गवाह स्वीकार करता है कि "हमारे द्वारा पूछताछ करने पर, वह चुप रहा"।

21. यह सच है कि इस गवाह से यह नहीं पूछा गया था कि उसने मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी क्यों नहीं भेजी थी। हालांकि,विद्वान वकील ने आधिकारिक रिकॉर्ड से बताया कि एफ.आई.आर. एक प्रति को मजिस्ट्रेट को 22.06.1994 तक नहीं भेजा गया था, हालांकि अदालत और पुलिस स्टेशन एक ही शहर में हैं। वीणा देवी (डी. डब्ल्यू.-1) और नर्मदा देवी

(डीडब्ल्यू-2)। के भी प्रमाण हैं। डी. डब्ल्यू.-1 ने दावा किया कि वह ८ बजे सुषमा से मिलने गई थी। उस समय सुषमा जीवित थीं। डी. डब्ल्यू.-2 ने जोर देकर कहा कि वह सुषमा से मिलने उनके घर गई थी तब लगभग 11 बजे तक सुषमा जीवित थी। उसने अपने पति को नाश्ता कराया था।

22. हम इन गवाहों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं लेकिन एक बात निश्चित है कि दोनों गवाह दावा करते हैं कि उन्हे दरवाजा बंद मिला। इसलिए उसने दो लोगों को यह कहते हुए बुलाया कि वबहू दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर वह दावा करती हैः "दो आदमी ने एक दरवाजे को धक्का दिया तो चिटकनी टूट गया; तो हमने देखा सुषमा पंखे से लटक रही थी। बच्चा रो रहा था। फिर दो आदमियों ने सुषमा को पंखे से उतार कर आंगन में सुला दिया ['दोनों व्यक्तियों को जबरन धक्का दिया गयादरवाजा का स्टॉपर टूट गया। वहाँ उन्होंने देखा कि सुषमा पंखे से लटक रही थी। बच्चा रो रहा था। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने शव को नीचे लाया और उसे आंगन में डाल दिया।

23. अपनी जिरह में उसने उन व्यक्तियों के नाम बिरजू मंडल और रामविलास बताए थे। जाँच एजेंसी ने कम से कम जाँच में अच्छा काम किया होगा। पड़ोसी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ऐसा किया गया है। डीडब्ल्यू 2 वह इस मायने में भी एक पड़ोसी थी। जो मृतक के घर बहुत पास रहती थी। यह ज्ञात नहीं है कि क्यों जाँच अधिकारी ने पड़ोसियों से

पूछताछ नहीं की, जिनमें से एक मृतक का रिश्तेदार था। घर की बारीकी से जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी की ओर से उदासीनता पैदा होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां चूक के कारण एक युवा महिला की मौत की जांच बिना किसी सजा के होनी चाहिए।

24. इसलिए, कई सवाल अनुत्तरित रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण लड़की की मृत्यु कहाँ हुई? घर के अंदर या बरामदे में? अगर वह घर के अंदर मर गई, तो क्या सड़क पर खड़ा कोई व्यक्ति का घटना को देखना संभव था ? बरामदे में शरीरकौन लाया ? घर के निवासी कौन थे ? घटना के बाद वे कहाँ गए ? वे कब गिरफ्तार हुए ? मृतक के बच्चे का क्या हुआ ? छत के पंखे की स्थिति, स्टॉपर की स्थिति (चिटकानी) आदि ? अदालत में सवाल अलग-अलग होते रहते हैं और एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति जांच अधिकारी होता है जिसने सबसे अधिक गैरजिम्मेदाराना और अनौपचारिक तरीके से कार्रवाई की है। हम उम्मीद करते हैं कि विभाग इस पर ध्यान दे।

25. राज्य ने अभियुक्त सं. 1 और 2. को बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। निचली अदालत ने पीडब्लू पर जहाँ तक उसके द्वारा आरोपित संख्या १को दी गई भूमिका है विश्वास करने से इनकार कर दिया । 2. यह एक और कारण है कि पीडब्लू-1 का प्रमाण पर विश्वास करना मुश्किल है। उसके साक्ष्य के बड़े हिस्से पर निचली अदालत द्वारा

अविश्वास किया गया है और निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। 26. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय से भी निराश हैं। यद्यपि विचारण न्यायालय ने संदर्भित किया है कि गवाहों ने, उन गवाहों के साक्ष्य की सत्यता, साक्ष्य का मिलान नहीं किया है ताकि उचित निष्कर्ष पर पहुँच सकें। समान रूप से प्रभाव उच्च न्यायालय के निर्णय का है। अभिलेख के संदर्भ में साक्ष्य की कोई गंभीर सराहना नहीं है। इसमें अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सभी तथ्य उच्च न्यायालय के लिए खुले थे और, इसलिए, उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती थी कि वह साक्ष्य और विशेष रूप से, अभिलेख के साथ-साथ सिद्ध दस्तावेजों में भी गहराई से जाए। गवाहों से मामले के अभिलेख और साक्ष्य में गहराई से जाने का प्रयास कोई गंभीर नहीं लग रहा है। आपराधिक अपील में अपीलीय न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथ्यों के सभी प्रश्न हैं अपीलीय न्यायालय के समक्ष खुलें। दुर्भाग्य से इस मामले में, हम इस मामले से निपटने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से इस तरह का कोई गंभीर प्रयास नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम सिद्ध साक्ष्य के साथ साक्ष्य की नए सिरे से जांच करना,जो हम आम तौर पर नहीं करते। हालाँकि, न्याय के हित में यह आवश्यक था।

27. परिणाम यह है कि सन्देह का लाभ सबसे पहले अभियुक्त को देना चाहिये और उस पर अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्धारितः निचली अदालत और अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णयों और दोषसिद्धि

के आदेशों को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त को सभी अपराधों से बरी कर दिया जाता है। बताया गया है कि वर्तमान में अभियु जमानत पर, उसका जमानत मुचलका रद्द किया जाता है।

बी. बी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती तोषिता मालानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।